बढ़ावा देने की पर्याप्त क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने इस क्षमता के उपयोग के संबंध में कतिपय सिफारिशें की हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने और खाद्य प्रसंस्करण एकक्रों के विस्तार के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा आवंटित की गई धनराशि पर्याप्त नहीं है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या यह भी सच है कि उचित भंडारण सुविधाओं के अभाव में उत्पादन का 30 प्रतिशत भाग, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3,000 करोड़ रुपए से 4,000 करोड़ रुपए तक है हर वर्ष नष्ट हो जाती है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस अनावश्यक हानि को रोकने के लिए देश की परिस्थितियों, सामर्थ्य व साधनों के तहत क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ताजे फल और संसाधित खाद्य पदार्थों के बारे में गठित एक्सपर्टीम फोकस ग्रुप ने अनेक सिफारिशें की हैं जिनमें शामिल हैं : कम ब्याज दरों पर वित्त का प्रावधान, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराना अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार भाड़ा दरों में कमी, अंगूर रक्षक कागज के शुल्क मुक्त आयात का प्रावधान, पैकिंग में सुधार आदि ।

(घ) और (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को 46 करोड़ रु० का आबंटन किया गया है जिसे उत्पादन तथा प्रसंस्करण यथा, प्रशीतन गृहों तथा प्रसंस्करण सुविधाओं, प्रशीतित परिवहन, विपणन नेटवर्क श्रमिकी की प्रशिक्षण, फलों, सब्जियों, कुक्कुरमुत्तों, मांस, अंडा तथा कुक्कुट, तथा ट्रना और अन्य मत्स्य प्रसंस्करण के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं का विकास जैसी अवस्थापना को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर खर्च करने का प्रस्ताव है । इन प्रयासों की कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडी) से भी बढ़ावा मिल रहा है ।

(च) और (छ) हालांकि, समुचित भंडारण सुविधाओं की कमी की वजह से फलों और सब्जियों को हुई हानि का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, फिर भी योजना आयोग के भूत पूर्व सदस्य डा० एम० एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में मई 1981 में खराब होने वाली कृषि मदों के बारे में गठित एक दल की रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया था कि कतिपय फलों और सब्जियों का लगभग 40% भाग, इन उत्पादों के लिए फसल पश्चात समुचित अवस्थापना सुविधाओं और संसाधन सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण बेकार हो जाता है । फलों तथा सब्जियों और खाद्य मदों के प्रसंस्करण की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने इन उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विविध कदम उठाए हैं ।

@@@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 3906, 28 अगस्त, 1993 से स्थानांतरित ।

Revival of Kribhco

@@@@ 4397-D. SHRI DIGVIJAY SINGH : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is fact that KRIBHCO is facing sickness due to its heavy invest ment with the finance company resulting in lack of growth opportunity;, and

(b) if so, what steps are contemplated by the Government to revive it ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Uniform Farm Marketing Policy

$4397-E. DR. NAUNIHAL SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal for an uniform farm produce marketing law for the agro-base industry of the country, if so, the details thereof:

(b) whether Government are aware that at present each State and Union Territory has its own farm produce marketing law and imposes varying rates of taxes on the dealers and buyers besides imposing stock limits, if so, the details thereof;

(c) whether Government are aware that this offer results in multiple taxation and avoidable harassment to the agro-base and agro-processing industry; and

(d) whether Government have taken any steps to rectify the maladies in the field of farm produce marketing, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE

©©©©Previously UnStarred Question 4065, transferred from 25-8-1993.

$Previously UnStarred Question 4422, transferred from 27-8-1993.